



# TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-11 Issue - 25

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad  
केन्द्र एवं उ०प्र० सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcbz.com

News of the Week	1731 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन और करीब दस लाख दुकानों को फ्री होल्ड करने की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार ने दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों पर दांव खेलते हुए दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में 'जहां झुग्गी वहां मकान' की नीति पर काम तेज करने जा रही है।	Inside Ghaziabad	पेज नंबर 2 जिले के विद्युत बकायेदारों से होगी 142 करोड़ की वसूली	पेज नंबर 5 Two former DM of Ghaziabad face probe...
------------------	---	------------------	---	--



### नोएडा टेंडर घोटाले में हुई गवाही पूरी

गाजियाबाद : सीबीआई कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के टेंडर घोटाले में सुनवाई हुई। कारोबारी रवि कंसल के बयान दर्ज होने के बाद गवाही पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए तारीख लगा दी। आरोपित यादव ड़क्षसह को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को डासना जेल से लाकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया।

### टैक्स घोटाले में निगम को क्लीन चिट

गाजियाबाद : नगर निगम के हाउस टैक्स घोटाले को लेकर हुए विवाद की जांच के मामले में निगम को क्लीन चिट की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी इससे पूरी तरह से पर्दा उठना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि अपर नगर आयुक्त समेत तीन अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण की जांच पूरी कर नगर निगम को क्लीन चिट दी है। उधर, नगर आयुक्त दिनेश चंद्र का कहना है कि मामले की जांच पूरी हो गई है।

### बदायूं के पूर्व सीएमओ ने किया सरेंडर

गाजियाबाद : सीबीआई की विशेष अदालत में बृहस्पतिवार को बदायूं के पूर्व सीएमओ ने पेश होकर सरेंडर किया। उनके वकीलों ने उसे जमानत दिलाने के लिए अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर उसे जमानत दी। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2008 में एनआरएचएम स्कीम के तहत लाखों रुपये की दवाएं जनपद बदायूं में खरीदी गई थी। इन दवाओं की खरीद फरोख्त में लाखों रुपये की हानि होने पर सीबीआई ने इस मामले की जांच की।

## प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं थैलेसीमिया रोगियों की संख्या : डा.तेजेंद्र सिंह

आरएचएएम (संकल्प स्वास्थ्य जागरूकता अभियान) व रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर, दिल्ली ईस्ट एंड तथा दिल्ली सफदरजंग क्लब द्वारा सूरजपुर स्थित आईईसी कॉलेज में थैलेसीमिया पर सेमिनार आयोजित

ग्रेटर नोएडा : आईईसी कॉलेज सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में बुधवार को थैलेसीमिया पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आरएचएएम (संकल्प स्वास्थ्य जागरूकता अभियान) व रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर, दिल्ली ईस्ट एंड तथा दिल्ली सफदरजंग क्लब द्वारा आयोजित सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि नोएडा सीएमओ डा.अनुराग भार्गव, थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3012 के चेयर डा.धीरज भार्गव, थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3011 की चेयर डा. तेजेंद्र सिंह व आईईसी कॉलेज के निर्देशक सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में लोगों ने डाक्टरों से सवाल-जवाब भी किए। इस दौरान मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। सेमिनार



को संबोधित करते हुए थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3011 की चेयर डा. तेजेंद्र सिंह ने कहा कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं और जो बन पाते हैं वो कुछ समय तक ही रहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार-बार खून चढ़ाना

पड़ता है। ये रोग अनुवांशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह रोग काफी कष्टदायक होता है। थैलेसीमिया के रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 10 हजार थैलेसीमिया के मरीज बढ़ रहे हैं। दस वर्ष पूर्व यह संख्या 2 हजार प्रतिवर्ष थी।



थैलेसीमिया दो तरह का होता है एक माइनर और दूसरा मेजर। दुनिया की कुल आबादी में 20 फीसदी लोग माइनर थैलेसीमिया से ग्रसित हैं। लेकिन जांच के अभाव में उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती है।...

शेष खबर व फोटो पेज 3 पर

### एसटीपी के पानी से बुझेगी आग, निजी कंपनियों में भी होगी आपूर्ति

साहिबाबाद : इंदिरापुरम के शक्ति खंड चार स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निजी कंपनियां पानी ले सकती हैं। इसके लिए जीडीए में आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं जीडीए अधिकारी अग्निशमन विभाग से भी बात करेंगे कि वह आग बुझाने के लिए एसटीपी से पानी लें। इससे एसटीपी से निकलकर बर्बाद होने वाले लाखों लीटर पानी की बचत की जा सके। ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों से सीवर का पानी इंदिरापुरम के शक्ति खंड चार स्थित एसटीपी में आता है। यहां से शोधित होकर पानी नाले के रास्ते हरनंदी नदी में बह जाता है। इस तरह रह रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर विभिन्न कामों के

लिए भूजल निकाला जा रहा है। इससे शहर में भूजल स्तर गिर रहा है। आने वाले दिनों में पेयजल खत्म होने की आशंका है। जीडीए ने भूजल को बचाने के लिए सड़कों पर छिड़काव और ड़क्षसचाई के लिए भूजल का प्रयोग करना बंद कर दिया है। जीडीए के टैंकर एसटीपी के पानी से सड़कों पर छिड़काव करते हैं, जिससे धूल न उड़े और वायु प्रदूषण न हो। इसके साथ ही सेंट्रल वर्ज में लगे पेड़ पौधों की धुलाई और ड़क्षसचाई भी एसटीपी के पानी से की जा रही है। जीडीए के अधिशासी अभियंता एके चौधरी का कहना है कि अग्निशमन विभाग से भी बात की जाएगी कि वह आग बुझाने के लिए इंदिरापुरम स्थित एसटीपी से पानी ले सकते हैं।

### Ghaziabad Development Authority begins land takeover

**Madhuban Bapudham**

**GHAZIABAD:** The Ghaziabad Development Authority (GDA) has started taking physical possession of land for its Madhuban Bapudham housing scheme. GDA intends to take over 100 acres of land in the next 10 days, officials said. “The enhanced land compensation has been paid to farmers through the district administration for which we had to take a loan of Rs 800 crore. Within 10 days, we will take physical possession of 100 acres of land of a total of 281 acres,” said Santosh Rai, secretary, GDA. GDA’s Madhuban Bapudham is spread in an area of 1,231 hectares which has 2,570 number of plots under different categories. There are over 254 MLA plots, 762 developed plots earmarked for farmers whose land were acquired and 1,554 plots for normal buyers on whom the increased land rates will be charged. GDA was forced to revisit land rates of plots after a group of farmers moved the Allahabad high court demanding higher land compensation.



## जिले के विद्युत बकायेदारों से होगी 142 करोड़ रुपये की वसूली

गाजियाबाद: जनपद के तीन हजार से अधिक के बकायेदारों से विद्युत विभाग 142 करोड़ की वसूली करेगा। इसके लिए विशेष डिस्कनेक्शन एवं बकाया वसूली अभियान 15 दिन तक लगातार चलाया जाएगा, जिसमें पुलिसबल के साथ विद्युत निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम शामिल होंगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे करीब 76 हजार बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। यूपीपीसीएल की ओर से विद्युत बकायेदारों के खिलाफ सख्ती के साथ वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के ऐसे

घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ 12 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिन पर तीन हजार रुपये से अधिक का बकाया है। जनपद के शहरी क्षेत्र की बात करें तो ऐसे 45 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 59 करोड़ 65 लाख रुपये बकाया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बकायेदार 31 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 82 करोड़ रुपया बकाया है। यानि जिले के 76 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर करीब 142 करोड़ रुपया बकाया है। इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए योजना तैयार की गई है।

### अधिकारी की पिटाई, लोनी के विधायक समेत 12 पर एफआइआर

लोनी : बलराम नगर कालोनी स्थित कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की पिटाई के मामले में लोनी विधायक और उनके 12 साथियों के खिलाफ लोनी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने आदि का आरोप विधायक पर लगा है। हालांकि विधायक ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के पीछे उनकी पार्टी के ही एक आला पदाधिकारी का हाथ बताया है। एसपी देहात के आदेश पर लोनी विधायक, प्रतिनिधि ललित शर्मा, सचिन और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

## रंग लाई टीबी विभाग की मुहिम, 90 बच्चों को लिया गया गोद

गाजियाबाद : क्षय रोग विभाग की मुहिम रंग ला रही है। विभाग के आह्वान पर अब तक जनपद के विभिन्न संगठन और उनसे जुड़े लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले 90 टीबी पीडित बच्चों को गोद लेने की घोषणा कर चुके हैं। 21 नवंबर को जिला एमएमजी अस्पताल में जनपद के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ विभाग की पहली मीटिंग में इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। उस दिन एसोसिएशन के अध्यक्ष हृदेश कंसल और जिला औषधि निरीक्षक पूरन सिंह ने दस-दस टीबी पीडित बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में हुई।

जिला टीबी फोरम की बैठक में आइएमए की ओर से 30, रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से 25, स्वयं सेवी संस्था आइएमडीटी की ओर से 10, आरएनटीसीपी की सहयोगी संस्था से डा. ताहिर ने पांच टीबी पीडित बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। जिला टीबी फोरम और टीबी टास्क फोर्स की बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डा. जेपी श्रीवास्तव ने जनपद गाजियाबाद की आरएनटीसीपी की उपलब्धियों, जैसे पब्लिक, प्राइवेट टीबी नोटिफिकेशन, सीबीनॉट मशीन टेस्टिंग, डीआर टीबी वार्ड में भर्ती एमडीआर और एक्सडीआर मरीजों और इन मरीजों के लिए आई नई दवा बीडाकुलीन की उपलब्धता से अवगत कराया।

### जिलाधिकारी ने ली सातवीं आर्थिक गणना की बैठक

गाजियाबाद : जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में सातवीं आर्थिक गणना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार प्रत्येक पांच साल में आर्थिक गणना का कार्य कराती है। आर्थिक गणना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की आर्थिक स्थिति का आंकड़ा प्राप्त कर भविष्य के लिए लाभकारी योजनाओं को बनाने का काम किया जा सके। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्य मोबाइल ऐप द्वारा जन सुविधा केंद्रों व सीएससी के माध्यम से कराया जाएगा।

### ड्राइविंग का प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं को मिलेगा रोजगार, मांगे आवेदन



मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने मंगलावार को ड्राइविंग में प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं के साथ विकास भवन सभागार में बैठक की। बैठक में 15 महिलाएं पहुंची, जिनसे कैब न चलाने की वजह पूछी गई। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की ज्यादातर महिलाओं ने कहा कि वह घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके बाद इनमें से छह महिलाएं ही ड्राइविंग करने के लिए तैयार हुईं। ड्राइविंग करने की इच्छुक अन्य महिलाओं से भी आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद जिन महिलाओं के पास

## सभी नौकरियों का सेवायोजन के पोर्टल पर होगा पंजीकरण

गाजियाबाद : रोजगार व बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा जुटाने के लिए सेवायोजन विभाग ने सभी नौकरियों के लिए से अपने पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी कर दिया है। यह पंजीकरण अभ्यर्थियों के साथ निजी संस्थानों व सरकारी विभागों को कराना होगा। यदि कोई निजी कंपनी बिना पंजीकरण के नौकरी देती है तो सेवायोजन विभाग को उसकी जांच कर रजिस्ट्रेशन कराएगा। हालांकि, पंजीकरण नहीं कराने पर कोई कार्रवाई तय नहीं हुई है। विभाग को पता नहीं चल पा रहा है कि जिले में कितने लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिल पा रहा है। क्योंकि

ज्यादातर लोग सेवायोजन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराए बिना ही नौकरी लगा लेते हैं। जनपद में रोजगार और बेरोजगारों की स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य सचिव ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कराने का आदेश दिया है। यह आदेश सरकारी, निजी, संविदा व आउटसोर्सिंग नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा। सरकारी विभाग और संस्थानों को भी पंजीकरण कराना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजीकरण के बाद उसका प्रिंट भी निकालना होगा।

### ईडब्ल्यूएस प्लैट आवंटन में घोटाले का आरोप

गाजियाबाद : इंदिरापुरम के न्यायखंड में ईडब्ल्यूएस प्लेटों के आवंटन में घोटाला होने का आरोप लगा है। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने प्रमुख सचिव आवास को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि वर्ष 1998 में आग में पत्रावलियां जलने का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से 400 से ज्यादा प्लैट आवंटित कर दिए गए। इससे जीडीए को करीब दस करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आरोप भी है कि आग लगने के बाद हुई जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस मामले में उन्होंने विजिलेंस जांच कराने की मांग की है। आग लगने पर हुई जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की गुहार लगाई है।

### उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का कारनामा, सवा लाख कस्टमर्स के पैसों का रिकॉर्ड किया गायब

नोएडा : पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की लापरवाही से सवा लाख उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि का रिकॉर्ड लापता हो गया है। नए नियमों के तहत सिक्योरिटी राशि बढ़ाने के बाद हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। नए नियम के तहत पावर कॉरपोरेशन सभी उपभोक्ताओं से 45 दिन के बिजली बिल की औसत राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करा रहा है। जिस उपभोक्ता के पास पुरानी सिक्योरिटी की रसीद है, उसकी सिक्योरिटी में से यह राशि काटी जा रही है। जिसके पास रसीद नहीं है उससे पूरी सिक्योरिटी राशि की वसूली की जा रही है। पावर कॉरपोरेशन के पास सिर्फ पिछले दस साल का रिकॉर्ड है,

जबकि नोएडा में वर्ष 1976 से बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं यानि 43 साल में से सिर्फ 10 साल का ही रिकॉर्ड पावर कॉरपोरेशन के पास है। पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पास पुराने दस्तावेज सुरक्षित होंगे। सबसे ज्यादा परेशानी घरेलू उपभोक्ताओं को हो रही है। कॉरपोरेशन ने नवंबर में सिक्योरिटी की राशि जोड़कर बिल भेज दिए हैं यानि 45 दिन के बिल की सिक्योरिटी राशि और एक माह का बिजली बिल एक साथ उपभोक्ताओं के घर पर पहुंचा है। इससे उपभोक्ताओं में बेचौनी है और उन पर एक साथ बिजली के बिल का बोझ बढ़ गया है।

### व्हीकल फ्री रोड बनाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी, पार्किंग खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस

गाजियाबाद : राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में शहर की पहली व्हीकल फ्री रोड बनाने के लिए जीडीए ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। दुकानों के सामने पार्किंग स्थल खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस दे दिया गया है। उनके वाहनों की पार्किंग के लिए दुर्बई मॉल के पीछे जगह खाली करा दी गई है। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटते ही रोड को व्हीकल फ्री बनाने का काम शुरू करा दिया जाएगा। नए साल में व्हीकल फ्री रोड का उद्घाटन करा दिया जाएगा।





## सामान्य रूप से शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र होती है करीब 120 दिन

**प्रथम पेज का शेष ...** सेमिनार को संबोधित करते हुए थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3011 की चेयर डा.तेजिंदर सिंह ने बताया कि सामान्य रूप से शरीर में लाल रक्त कणों की उम्र करीब 120 दिनों की होती है। परंतु थैलेसीमिया के कारण इनकी उम्र सिमटकर मात्र 20 दिनों की हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं एवं इनकी जीवन अवधि 120 दिनों तक ही सीमित होती है। इस दौरान सीएमओ डॉ अनुराग भार्गव, डिस्ट्रिक्ट 3011 चेयर थैलेसीमिया डा.तेजिंदर सिंह, थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3012 के चेयर डा.धीरज भार्गव, आईईसी कॉलेज के निर्देशक सुनील कुमार के अलावा रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली ईस्ट एंड के अध्यक्ष अनिल छाबड़ा व सचिव दयानंद शर्मा, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सफदरजंग के सचिव रतन मोना पुरी, रोटेरियन अपूर्व राज, आरएचएएम से श्रीमती अंजली बावा, आईईसी कॉलेज से शरद माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।



नोएडा सीएमओ डा.अनुराग भार्गव ने भी लोगों को थैलेसीमिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार थैलेसीमिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके अनुसार हमें जागरूक होने की जरूरत है। जिस प्रकार हम शादी से पूर्व लड़का-लड़की की कुंडली मिलाते हैं उसी प्रकार हमें शादी से पूर्व थैलेसीमिया का भी टेस्ट कराना चाहिए। जिससे पता चल सके कि कोई इस रोग से तो पीड़ित नहीं है।



थैलेसीमिया डिस्ट्रिक्ट 3012 के चेयर डा.धीरज भार्गव ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों में रोग के लक्षण जन्म से 4 या 6 महीने में ही नजर आने लगते हैं। बच्चे की त्वचा और नाखूनों में पीलापन आने लगता है। आंखें और जीभ भी पीली पड़ने लगती है। उसके ऊपरी जबड़े में दोष आ जाता है। दांत उगने में काफी कठिनाइयां होने लगती हैं। त्वचा पीली, यकृत और प्लीहा की लंबाई बढ़ने लगती है तथा बच्चे का विकास एकदम रुक जाता है। यदि माता-पिता थैलेसीमिया माइनर हैं, तब बच्चों को इस बीमारी की आशंका अधिक रहती है। अगर माता पिता में किसी एक को यह रोग है तो बच्चे में रोग के मेजर होने की आशंका नहीं रहती। माइनर का शिकार व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है और उसे कभी इस बात का आभास तक नहीं होता।



## नए साल में एक विलक पर मिलेगी इंदिरापुरम की संपत्तियों से जुड़ी जानकारी

गाजियाबाद : नए साल में इंदिरापुरम की संपत्तियों से जुड़ी जानकारी एक विलक पर ली जा सकेगी। आवंटी घर बैठे बकाया राशि, भुगतान, रजिस्ट्री, म्यूटेशन समेत जरूरी जानकारी जुटा सकेंगे। यहां की संपत्तियों का ब्योरा वेक्टर मैप पर अंकित कर दिया गया है। जनवरी में इस वेक्टर मैप को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। लखनऊ स्थित रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर इस काम को अंजाम दे रहा है। उन्हें कुछ

दिक्कतें आ रही हैं। इस सेंटर के विशेषज्ञों ने बुधवार को जीडीए अधिकारियों के साथ बैठक की। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने संपत्ति, नियोजन और अभियंत्रण अनुभाग के अधिकारियों को दिक्कतें दूर करने में सहयोग करने का निर्देश दिया है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदिरापुरम से शुरुआत की जा रही है। बंगलुरु विकास प्राधिकरण की तर्ज पर यह काम किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग

की मदद से इंदिरापुरम का बेस मैप और वेक्टर मैप बनाया गया है। वेक्टर मैप में प्रत्येक संपत्ति की बाउंड्री दर्शायी गई है। इस कॉलोनी की संपत्तियों की 1.62 लाख फाइलों को स्कैन कर वेक्टर मैप पर अटैच किया गया है। वीसी ने बताया कि रिमोट सेंसिंग से जुटाए गए नक्शे से जीडीए के नक्शों का मिलान नहीं हो पा रहा है। जिस जगह प्लॉट दिख रहा है। जीडीए के नियोजन अनुभाग के नक्शे में वहां कुछ नहीं दर्शाया गया है।

## एप पर हेड मास्टर बताएं स्कूल की वास्तविक स्थिति, बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रेरणा एप

गाजियाबाद : शासन परिषदीय स्कूलों की कायाकल्प करने के लिए एक एप बनाया है। इस प्रेरणा एप के माध्यम से स्कूल के हेड मास्टर स्कूल की वास्तविक स्थिति के बारे में शासन को जानकारी देंगे। इससे स्कूल की खामियां व स्कूल के ढाचे को ठीक किया जा सकेगा। हेड मास्टर को स्कूल से जुड़ी 23 विकल्पों को भरकर उनके हां या नहीं का

जवाब देना होगा। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रेरणा एप डाउनलोड करने के आदेश दिए थे, लेकिन शिक्षकों के विरोध के कारण अभी तक एप डाउनलोड नहीं किया गया था। ऐसे में अब प्रेरणा एप के अंतर्गत एक और एप कायाकल्प दिया गया है।



## EDITORIAL

## A precedent: on apex court ruling on Essar Steel

The Supreme Court's judgment on Friday in the matter of Essar Steel's bankruptcy is a landmark in the short history of insolvency and bankruptcy resolution in India. Apart from clearing the way for eventual sale of Essar Steel to ArcelorMittal, the verdict has clarified on important aspects of insolvency resolution that had been interpreted variously by the National Company Law Tribunal and the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT). First off, the apex court has upheld the primacy of financial creditors over operational creditors in the repayments waterfall, and rightly so too. It is the financial creditors who provide capital to an enterprise and their interests are secured in the form of collaterals on the firm's assets. Operational creditors, who are largely suppliers of goods and services, are unsecured creditors and they cannot claim equality or precedence over financial creditors. Second, the Supreme Court has shown the NCLAT, which was attempting to appropriate the role of the Committee of Creditors (CoC) in an insolvency resolution, its place. The ruling is clear that the CoC is supreme when it comes to deciding on commercial issues, including the repayment waterfall, in an insolvency resolution. These two clarifications should alone help in quickening a number of other cases, big and small, that are stuck in the insolvency courts across the country.

The apex court has also held that the 330-day limit for resolution is not sacrosanct. This will ensure that creditors are not pressured to accept a below-par deal due to paucity of time. With critical aspects of the law clarified, there may also not be reason to fear that entrenched promoter-defaulters can misuse the unlimited time now available to them. With the go-ahead given to the sale of Essar Steel, it is expected that banks will recover over 90% of the over ₹40,000 crore that the company owes them. Operational creditors are set to receive close to ₹1,200 crore. This should clearly help improve the financial position of weak public sector banks and bolster profitability as the Essar dues were fully written off by them. Shares of banks such as State Bank of India, and Punjab National Bank rallied following the verdict. More importantly, the decision, it is believed, will serve as a useful precedent when it comes to deciding on future bankruptcy cases. The insolvency and bankruptcy process is still young in India. There is a long way to go yet, especially in the matter of recovery percentages. The Essar Steel resolution has raised the bar but the overall recovery in all cases that have been adjudicated is less than 50%. This has to improve, along with the time taken for resolution, because significant capital is locked up in bankrupt companies.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

## 20,000 new flats in Greater Noida get nod for dual power meters

**GREATER NOIDA:** Almost 20,000 flats across 17 under-construction highrise apartment complexes in Greater Noida are set to get dual meter connections once the projects are completed. Recently, the approvals came from the Noida Power Company Limited (NPCL), which provides electricity in Greater Noida. The demand was raised so that the excessive power charges levied on them in complexes could be controlled.

## Two held in Ghaziabad for demanding Rs 5 lakh extortion from junior engineer

**GHAZIABAD:** Two men, who were allegedly planning to extort Rs 5 lakh from a junior engineer with the irrigation department, were arrested on Wednesday following a gunfight in Modinagar area. The irrigation department official had gone to address where he was supposed to handover the money to the duo when the shootout took place. Neeraj Kumar Jadaun, SP (rural), Ghaziabad, said the police had information and laid a trap. A few Rs 2,000 notes were packed along with several white papers between them and when the duo came

to take money, the police caught them. "The duo snatched the bag from the junior engineer and tried to flee the spot but the police surrounded them. They were asked to surrender but the men allegedly fired at the policemen and tried to run away. The policemen fired a few shots and the duo, identified as Akash (30), from Aligarh district, and Ravi Sharma (35), from Ghaziabad, suffered bullet injuries in their legs," Jadaun said. Surajpal Singh, the Jal Nigam officials, told TBC: "On November 15, at 6.30 in the morning, a person

called me and asked me if I was Surajpal Singh. When I said yes, he asked me to give him Rs 56 lakh. I refused to give him the money and threatened me saying that he will kill my family members," he added. "After that, he kept calling me from several numbers and kept threatening me. On November 18, the man called me again and said if I did not pay up, he will kill me and my wife. I contacted the police and lodged a complaint. The police assured me and my family that we would be safe and then they made a plan to lay the trap.

## Suraksha's Jaypee bid gets higher score than NBCC's, over to voters

**NOIDA:** Before voting by homebuyers and other financial creditors for the insolvency resolution of Jaypee Infratech Limited, Suraksha Realty has pipped state-run NBCC in the initial evaluation of bids to complete flats launched by the beleaguered company. An analysis of proposals conducted by the RBSA, which was appointed by insolvency resolution professional Anuj Jain, Suraksha had an overall score of 27 while NBCC scored 20. The assessment was done on a score of 100 and the points have been awarded on what the companies propose to bring

on board in terms of upfront cash inflow and their debt resolution policy towards banks, homebuyers, penalties, debt-asset swaps, liquidation of assets and completion timelines. The primary areas where Suraksha scored over NBCC are fund infusion and debt-asset swaps with lenders. Suraksha has offered to bring in Rs 2,000 crore as working capital to complete construction in the next three years and will retain the Yamuna Expressway with itself. The Mumbai-based realtor has also proposed to set aside land worth Rs 100 crore for the welfare of homebuyers.

## Used MP sticker on SUV, one held

**NOIDA:** In a major blow to the ongoing investigation in the home guard scam, muster rolls of personnel deployed in Gautam Budh Nagar since 2014 were destroyed in a fire that broke out at the district commandant's office in the early hours of Tuesday. Six home guard officials have been detained for questioning, police said. The detention of the six officials, including three platoon commandants, came hours after the Yogi government ordered a probe into the destruction of the attendance logs, which police suspect were deliberately set ablaze.

## Officer allowed rules to be flouted for home guard attendance

**NOIDA:** Investigations into the home guard scam have revealed that divisional commandant (Aligarh) Ram Narayan Chaurasia, who was arrested earlier this week, had allowed non-regular platoon commandants to prepare muster rolls and duty rosters. Police believe the scam estimated to be worth Rs 3-4 crore is not restricted to Gautam Budh Nagar alone but had spread its tentacles to other parts of the state. Sources said a similar modus operandi had been followed to carry out the fraud in other districts as well. Under the scam, these non-regular platoon commandants would

prepare inflated attendance for home guards, forge signatures of station house officers and submit the list to the home guard department to get salaries disbursed. Police believe at least 50% of the salary disbursed to guards in seven police stations in May and June was based on fake attendance. The commandants would, in turn, get a share of the extra salary the guards got. Three of the accused arrested from Noida Montu Kumar, Shailendra Kumar and Satveer Yadav were not on the government's payroll. Despite that, Chaurasia had allowed them to prepare duty roster

and muster rolls. Rules under the home guard department authorise only regular platoon commandants to prepare muster rolls. Home guards are paid according to the number of days they attend work. Noida police chief Vaibhav Krishna said Chaurasia had in 2018 issued a letter, authorising even non-regular platoon commandants to prepare attendance rolls, in the two years he was posted as the district commandant in Gautam Budh Nagar. "Legally, it was incorrect. But the then district commandant had authorised them to prepare muster rolls, bypassing rules," he said.



## Out of jail, youth shot on busy road

**GHAZIABAD:** A 25-year-old man was shot dead by two unidentified bike-borne assailants on the busy Railway station road in Kavi Nagar on Saturday afternoon. The deceased, Vinod Kumar alias Bhajji, was a resident of Sector 23 in Sanjay Nagar. “The deceased was a criminal. More than 15 cases of robbery, theft and some under the NDPS Act were registered against him in Delhi-NCR. Two months back, he got out of jail,” a senior police officer said. Vinod’s father Rajaram said his son used to live separately

but came home every 10 days. Around 11.30 am, he went outside the house on his bike. “He told his mother that he was going to meet one of his friends and will be back for dinner. Fifteen minutes later, I got information about his death,” said the father. Anil Kumar Shahi, the SHO of Kavi Nagar police station, told TBC that two persons on a white Apache accosted Vinod and asked him to stop the bike. As soon as he did, the two men fired at him. “Preliminary investigation suggests gang rivalry as the reason behind the murder on a busy road during the day,” he added.

## Residents of Noida, Greater Noida complain of pipeline leak

**NOIDA:** The Noida Authority on Tuesday held a mediation meeting between the Apartment Owners’ Association (AOA) of Supertech Cape Town and the builder. The AOA raised issues of water and electricity connection, open parking, handover of society and outsourcing of community centres to vendors, among others. The additional CEO (ACEO) has directed the builder to submit a written plan with the timelines to execute all the changes in the next three days. “Besides these, the builder has taken 535 water connections so far, while over 4,000 families are living here now.

## Two former DM of Ghaziabad face probe in Rs 27 crore land scam

**G H A Z I A B A D / LUCKNOW:** The state government on Tuesday approved action against two former district magistrates of Ghaziabad, more than two years after they were indicted in a Rs 27crore scam related to acquisition of land for the Delhi-Meerut Expressway. The decision was taken at a state cabinet meeting held in Lucknow, officials said. Uttar Pradesh home secretary Bhagwan S Srivasatava said that the decision to initiate criminal proceedings against former DMs Vimal Sharma and Nidhi Kesarwani, along with other officials posted in Ghaziabad, was taken on the



September 2017 recommendations of then Meerut divisional commissioner Prabhat Kumar. “We would seek opinion of legal experts and decide whether a CBI inquiry is required, otherwise state police would be asked to carry out the investigation,” Srivasatava said. The scam pertains to purchase of agricultural land at throwaway prices from farmers of Dasna, Rasoolpur Sikrod, Kushalia and Nahal

## No firecrackers at weddings: Noida reminds revellers of NGT directive

**NOIDA:** The Gautam Budh Nagar administration issued a special notice for wedding parties on Saturday, asking them not to burst firecrackers as it would violate the guidelines of the National Green Tribunal (NGT). The district administration had organised an awareness meet last week and informed all wedding lawns and community centre operators that allowing bursting of firecrackers was illegal. “We have noticed that despite the ban, the firecrackers are being burst for weddings and other such festivities. There are several

weddings planned in the district on Saturday and we have requested all the wedding venue officials, organisers and the families involved not to burst firecrackers, otherwise, penal action could be taken against them,” said Shailendra Mishra, the city magistrate. As per EPCA’s directions, bursting crackers is banned for the entire winter season. In the past two weeks, the GB Nagar district administration has filed five separate complaints against grooms and wedding organisers for bursting crackers during events.

## Lotus buyers vote against IRP, interim administrator named

**NOIDA:** A majority of homebuyers in the stalled Lotus brand projects Panache and Boulevard have voted for the removal of the two National Company Law Tribunal (NCLT)-appointed insolvency professionals. The tribunal has appointed an interim administrator till new insolvency professionals are named, officials said. TBC has learnt that a total of 2,185 homebuyers registered their vote through a mobile-based application. The voting results were submitted to NCLT on Wednesday in a sealed envelope by the investors.

## Man jumps to death at Golf Course Road metro station in Noida

**NOIDA:** A 25-year-old man from Delhi jumped to death at the tracks of Golf Course Road metro station early on Saturday morning. Commuters faced delay in services along Blue Line between Noida Electronic City and Karol Bagh for about an hour from 9am to 10am. Police informed that the man, identified as Rupaksh Paul, son of Sanjay Paul, was a resident of Bhagwan Das Road in Delhi. He was waiting for the train and made a run towards it, jumping right after the train entered the platform, officials informed. The man was hit by the train and was thrown

towards the tracks. “It is clear from the CCTV footage that he jumped in front of the train and was not pushed by anyone else. Family members said that Rupaksh was visiting a friend in Noida on Friday and had said that he would return on Saturday. However, they did not know which friend and we have not identified him yet,” said Neeraj Mallik, station house officer, Sector 39. He added that the family members did not know of any reason for the deceased to be disturbed and they also did not know of what happened at the friend’s place whom he was visiting.

## Abduction bid of man goes wrong as assailants get stuck in heavy traffic

**NOIDA:** An abduction bid of a 30-year-old man went wrong when the assailants, fleeing in a car, were first caught in heavy traffic on the Noida-Delhi road and then their vehicle broke down, police said on Wednesday. The victim escaped from the clutches of the assailants when they got down from their Honda City to stop a random Maruti WagonR to flee the spot, officials said. Six people, including the four who were in the car, were arrested on Tuesday on charges of kidnapping, robbery, among others, a police official said.

## 300 fines in a month but there’s no stopping wrong-side driving here

**NOIDA:** Waiting for a flat after investing in it is nothing new for a buyer in the National Capital Region. However, in the case of Orizzonte, a project by the Horizon Group in Greater Noida’s Knowledge Park 3, its manhandling of funds by the company that has stalled work. The project was to have 364 residential units spread over three towers along with a hotel and commercial space in the same complex. The total units that are supposed to come up is about 1,800. Bookings were made in 2013 and the project was to be completed within three years.

By 2018, all flats were supposed to be handed over. Already delayed, the developer has now cited internal feud as the cause. The company’s director has claimed that work on the project will resume in January 2020. The directors of Horizon Concept Infra Private Limited, which is building Orizzonte, are Jeevesh Sabharwal and Nitant Verma. The promoters have offered a monthly return on the amount invested by buyers until possession is given. Not much work has progressed since the foundation for the project was laid in 2013.



## In Ghaziabad, cyber crime cases up by 90 times in 4 years

**GHAZIABAD:** The city, which recorded only 24 cases of crimes under the Information Technology (IT) Act in 2015, has registered 2,133 incidents till August this year. According to police data, Ghaziabad has seen a steep rise – around 8,785% – in the number of cyber crime cases in the past few years. For instance, the number of FIRs related to cyber crime lodged last year was 1,935. Police said that in 2018 and till August 2019, the number of persons arrested under the IT Act from the district was 30 and 20, respectively. In the 2,383 cyber

crime cases reported between 2015 and 2018, people lost over Rs 1 crore to fraudsters. According to police officers, around 40 per cent of cyber fraud cases were lodged by private firm employees and 20 percent of the registered complaints were made by women who had not received formal education. A senior police officer in the cyber cell said in 85 per cent of the cases, the accused were duped by people who claimed to have called on behalf of some bank. “When police trace such phone numbers, they usually belong to Jharkhand, Nepal,

Afghanistan and other places,” he said. Meanwhile, 325 cases were registered between 2015 and 2018 against people for objectionable posts on social media, of which 52 persons were arrested. Till August this year, 229 cases relating to objectionable social media posts were reported in the district. Ten people have been arrested, police data stated. As per police records, 50 cases of hacking and data leaks were reported between 2016 and 2018 and in 2019, 17 cases have been reported so far. Manish Kumar Mishra, SP (city) and head of Cyber-

Forensic Laboratory in Ghaziabad said that most of the frauds are related to online shopping done via credit and debit cards. “People very easily reveal their card details to fraudsters who take advantage of that,” he added. Police said, in 25 percent of the cases, victims claimed that there was a withdrawal of money even when they didn’t use their ATM cards. Some of the recent incidents have put the focus back on conversations around how to be vigilant while using bank cards to ensure that they are not misused.

## No wrong-side driving, Noida residents say with a smile and a chocolate

**GREATER NOIDA:** Four years and two months after Mohammad Akhlaq was murdered by a mob in front of their eyes, in their house in Dadri’s Bisada village, his family came together on Sunday not to grieve or discuss court proceedings but for a “mubarak mauka” (an occasion of joy). It was the wedding of Shaista (24). Akhlaq’s youngest daughter, who was displaced with the rest of her family from the house that had forever been home after his lynching and subsequent communal tension, married a Delhi-based civil engineer in a ceremony that was hosted at a banquet hall



in Ghaziabad’s Muradnagar. Akhlaq’s younger brother, Jaan Mohammad, told TBC that the family of the groom, Mehboob Alam Saifi, is from Pilkhuwa in Hapur district. The match was proposed four months ago by a relative of Akhlaq’s elder brother Afzal Ahmed. The marriage was finalised last month in a traditional “laal pattar” ceremony. On Sunday, Shaista, resplendent in a red attire, and Mehboob exchanged vows as their families blessed the couple.

## After Bike Bot, another Ponzi scheme that cheated 11,000 comes to the fore

**GNOIDA:** After Social Trade, Go Way, Bike4U, MIP Cabs and Bike Bot, another Ponzi scheme has possibly cheated as many as 11,000 people across the country. The company JSB NCR Tourism Limited which started in September 2018, floated at least five different schemes that involved a one-time investment in the range of Rs 52,500 and Rs 3.67 lakh. The modus operandi was similar to some of the earlier scams the investors were promised hefty returns from the profits made by the taxi service. The returns promised were in the range of Rs 10,250 and Rs 86,750 every month. Investments started flowing in around November-

December last year from across the country, including Delhi-NCR, parts of UP, Haryana, Maharashtra, Rajasthan and Punjab. But they stopped after April 2019. The company had even launched an app called TAXIJSB and its schemes were advertised on huge hoardings at Pushpotsav an annual event held by the Greater Noida Industrial Development Authority and the Floriculture Society of Noida. OP Pachauri, one of the investors from Dadri and a complainant in the case, said when the returns stopped and investors started protests, the company called a meeting and handed over cheques to some of them.

## Akhlaq’s 24-yr-old daughter marries Delhi engineer

**GREATER NOIDA:** Four years and two months after Mohammad Akhlaq was murdered by a mob in front of their eyes, in their house in Dadri’s Bisada village, his family came together on Sunday not to grieve or discuss court proceedings but for a “mubarak mauka” (an occasion of joy). It was the wedding of Shaista (24). Akhlaq’s youngest daughter, who was displaced with the rest of her family from the house that had forever been home after his lynching and subsequent communal tension, married a Delhi-based civil engineer in a ceremony that

was hosted at a banquet hall in Ghaziabad’s Muradnagar. Akhlaq’s younger brother, Jaan Mohammad, told TBC that the family of the groom, Mehboob Alam Saifi, is from Pilkhuwa in Hapur district. The match was proposed four months ago by a relative of Akhlaq’s elder brother Afzal Ahmed. The marriage was finalised last month in a traditional “laal pattar” ceremony. On Sunday, Shaista, resplendent in a red attire, and Mehboob exchanged vows as their families blessed the couple. Akhlaq’s family, including his wife Ikraman, daughter Mumtaz, sons Mohammad

Sartaj and Danish, and brothers Jameel Ahmed, Afzal Ahmed and Jaan Mohammad, were present. Mehboob was accompanied by his relatives and friends too. A few members of Samajwadi Party, including Ashu Malik, were also present at the wedding. The family said Malik was a neighbour. On September 28, 2015, a mob had lynched 52-year-old Akhlaq over suspicions that he had stored and consumed beef in his house, an incident now known nationwide as the Dadri mob lynching. They were all arrested within 10 days and later granted bail. One of them,

Ravi, died in judicial custody. The incident had triggered communal tension in Bisada village. Akhlaq’s family members subsequently left on October 17 the same year. They now live in government accommodation in Delhi’s Subroto Park. Shaista, who is an intermediate pass, was a key eyewitness in her father’s murder case. In 2016, she, along with several other family members, including Akhlaq, was booked for alleged cow slaughter. Jaan Mohammad told TBC that Mehboob was fully aware of the case and had entered the alliance with a promise of support and faithfulness.

### हेल्प लाईन नंबर

#### गाजियाबाद प्रशासन

डीएम –	2824416
आवास –	2820106
एडीएम (सिटी) –	2828411
एडीएम (प्रशासन) –	2827016
सिटी मजिस्ट्रेट –	2827365
आयकर विभाग –	2714144
पासपोर्ट कार्यालय –	2721779

#### पुलिस अधिकारी

एसएसपी –	2820758, 9643322900
पुलिस अधीक्षक नगर –	2854015
पुलिस अधी. यातायात –	2829520
सीओ प्रथम –	2733070
सीओ द्वितीय –	2791769
सीओ एलआईयू –	2700925
सीओ लोनी –	3125539

#### जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए –	2791114
जीडीए सचिव –	2790891

#### अस्पताल

सी.एम.ओ. –	2710754
सी.एम.एस. –	2730038
आपातकालीन –	2850124
कोलम्बिया एशिया –	3989896
यशोदा अस्पताल –	2750001-04
गणेश अस्पताल –	4183900
संतोष अस्पताल –	2741777
सर्वोदय अस्पताल –	2701694
नरेन्द्र मोहन अस्पताल –	2735253
जिला अस्पताल (एम्बुलेंस) –	2730038
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) –	2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल –	4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर –	43075600

#### बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) 2755777

#### अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम –	2734906
कोतवाली –	2732099
जिला कन्ट्रोल रूम –	2766898

#### पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम –	संदीप कुमार सिंह – 9643322921
एसएचओ लिंक रोड –	लक्ष्मी सिंह चौहान – 9643322924
एसएचओ –	साहिबाबाद – जितेंद्र कुमार सिंह – 9643322923
एसएचओ खोड़ा –	सतेंद्र प्रकाश – 9643322922
कोतवाली –	2732088
सिहानी गेट –	2791627
कविनगर –	2711843
विजयनगर –	2740797
इंदिरापुरम –	2902858
लोनी –	2600097
अग्निशमन विभाग –	2732099
	9818702101

रेलवे इन्कवायरी – 131

#### नगर निगम

नगरायुक्त – 2790425, 2713580

#### विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

#### पूछताछ

रेलवे कस्टमर –	2797840, 139
रिजर्वेशन –	8888
रोडवेज इन्कवायरी –	2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।

**Phone No.:**  
**0120-4561000**



DSGMC opens turban bank to motivate young Sikhs to wear turban

**AMRITSAR:** Aiming to motivate Sikh children to take pride in sporting turban, the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) has set up turban bank in Delhi. DSGMC chief Manjinder Singh Sirsa said on Sunday the turban bank has been established in Gurdwara Bangla Sahib in Delhi to mark the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev. “Sikh children who can’t afford to buy a turban can get one for themselves for Rs 50,” he said adding that the nominal fee was charged so that the recipient could feel that he

“bought” the turban. Normally, rubia, voile or malmal cloth is used for a Sikh’s turban, which ranges between six to eight meters in length and costs around Rs 400 to Rs 550, excluding the tailoring cost. “We have already given 500 turbans. Over 1,000 Sikhs have donated turbans for the noble cause,” said the DSGMC president. He said DSGMC would set up similar turban banks in all the 10 gurdwaras under its management. he also said they would also motivate Singh Sabha’s who run local gurdwaras to open turban banks in their respective areas.

Gujarat DFS to submit report in Noida home guard salary fraud

**AHMEDABAD:** The Directorate of Forensic Sciences (DFS) at Gandhinagar on Wednesday sent a team to Noida in Uttar Pradesh to probe a fire incident at Gautam Buddh Nagar. The fire incident, which took place on November 19, gutted crucial evidence in form of muster rolls in multi-crore home guards scam currently under probe. “A team of officers from DFS was sent to Gautam Buddh Nagar to collect samples from the fire site and give an opinion on whether it was case of an arson or natural phenomenon.

Month after MCG restarted work on Chauma Road, stretch still a nightmare

**GURUGRAM:** A biker with a mobile phone pressed between his ears and his left shoulder rides down bumpy Chauma Road but his multi-tasking skill fails him as he hits a deep pothole and skids. A fruit-seller stationed outside the gates of Delhi Public School, Ghaziabad rushes to help him. “Apart from selling fruits, assisting bikers who fall down here, is my daily job,” laughs off Omkar, a migrant from Bihar. Just like Omkar, the residents of the area have become used to bikes skidding and vehicles breaking down on this painfully uneven 150m stretch between the school intersection and Chauma

Noida, volunteers at odds on animal shelter supplies

**NOIDA:** Over the past few months, the city’s only animal shelter has seen food and medical supplies taper off. All because of a “pending investigation” into how the shelter is run. The Noida Authority, insists supplies have been restored but volunteers at the shelter said they haven’t had enough supplies coming in. “Food is in short supply. Most animals at the shelter are sick. Over the past few months, the number of blood tests has gone down significantly. “However, we have released funds for all supplies to be restocked.

Woman choked to death in Greater Noida, younger son prime suspect

**GREATER NOIDA:** A 50-year-old woman was allegedly strangled to death by her 15-year-old son at their home in Dhoom-Manikpur village of Greater Noida on Saturday. Police said the woman, had several “irritating habits”, and would wake up in the middle of night to ask for tobacco. She lived with her two sons and husband, who works as a security guard with a private agency in Chapraula area. Their elder son, too, works as a guard with a company. The woman’s repeated demands for tobacco would upset everyone in the family, cops said. Her

younger son is the prime suspect because her husband and elder son were away at work when the alleged murder took place. There was no evidence of burglary, too. It was the husband who saw her lying motionless on the cot at their home. Their younger son was also sleeping in the same room, he apparently told the cops. The husband, however, has ruled out his son’s involvement in the murder, and has lodged a complaint against unknown persons. The family is from Etah, but has been staying in Greater Noida for the past several years.

PVR staffer found dead in Noida mall

**NOIDA:** The body of a 48-year-old man working with PVR Cinemas was found on the second-floor terrace of Mall of India in Sector 18 on Friday morning. Bhuvan Chandra Sharma is seen going up to the fifth floor multiple times in the mall's CCTV cameras but there is no visual evidence of what happened after that. The area from where Bhuvan fell - a raised platform behind Audi 6 - is not in the cameras' range. Neither this area nor the place where his body was spotted is accessible to visitors. They are only used by mall employees.

Auto driver dumps injured passenger on road, detained

**GREATER NOIDA:** An autorickshaw driver was detained on Thursday for deserting a 28-year-old passenger whom he presumed to be dead after an accident that occurred on Wednesday night. The matter came to light 24 hours after police found the victim’s mobile phone and the broken down auto-rickshaw in a forest area near Sharda University in Surajpur. The victim Satish Bodaki’s nephew told TBC that an unknown person had called him from Satish’s mobile phone on Wednesday night and informed him that he had met with an

accident in Devla. “The caller said he is taking him to Naveen Hospital. However we could not find him when we reached there. Later, we checked all the hospitals in the nearby locations but failed to recover him,” he said. He added that around 9pm, he got a call from the cops saying that they have got Satish’s mobile phone. “A passerby told us about the accident. When we reached the spot, the caller told us that the auto driver took the passenger to a hospital since he was grievously injured,” said Dileep Singh, senior sub-inspector at Surajpur police station.

UP Power Employee Trust routed funds into DHFL through non-existent broking companies: EOW

**MEERUT:** Of the 14 brokerage firms used by UP Power Sector Employees’ Trust to route investments in DHFL, five were found to be front companies existing only on paper and the rest had no broking experience according to the findings of a probe by the Economic Offences Wing (EOW) of Meerut. According to EOW SP Ramsuresh Yadav, these 14 firms were used to invest the corporation employees’ provident fund in the delinquent home financier, whose board was superseded by the RBI on Wednesday.

No place to dump waste, it piles up along Hindon river

**GNIDA:** In stark violation of National Green Tribunal (NGT) norms, residents of Haibatpur and Bahlolpur in Bistrakh block and about 50 families from neighbouring Sai Upvan society have raised concerns regarding garbage dumping in Hindon river with no action from the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA). “There is no provision of garbage disposal around villages Haibatpur and Bahlolpur and surrounding areas. As a result, people dump garbage in the Hindon which is against the NGT rules,” said Nivedita Sarangi, a resident of

Sai Upvan society. Another resident of the society, Gopal Pathak, maintained that the Surajpur dust ground is around 20 to 25 km from the area. “People living in these areas dump garbage either on the road or in the river. We have raised many complaints against the matter so that this practice can be stopped, but no action has been taken by the authority so far,” said Pathak. While the area mostly has low income group housing complexes, senior citizens suffer the most due to continuous foul smell, pollution and respiratory issues.



इंदिरापुरम में अतिक्रमण के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण चलाएगा अभियान

साहिबाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) एक दिसंबर से इंदिरापुरम की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। जीडीए कई बार अतिक्रमण हटा चुका है लेकिन दुकानदार दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रमण की वजह से यातायात प्रभावित होता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। इंदिरापुरम की अधिकांश सड़कों के फुटपाथ पर दुकानें लगी हैं। इन दुकानों पर आने वाले लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर देते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है। इतना ही नहीं शाम को पीक आवर में जाम भी लगता है।

## मेरठ एक्सप्रेसवे घोटाला में लेखपाल से लेकर अधिकारी तक सबकी होगी जांच

गाजियाबाद : दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस वे घोटाले में प्रशासन स्तर पर होने वाली जांच में लेखपाल से लेकर अधिकारियों तक के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। इस संबंध में शासन की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने जिलाधिकारी को आदेश दिए। जिलाधिकारी से चार बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाधिकारी को प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट शासन को देनी होगी, जिसे प्रधानमंत्री ऑफिस भेजा जाएगा। इस परियोजना के डासना, नाहल, कुशालिया और रसूलपुर सिकरोड गांव में नोटिफिकेशन के बाद रिटायर्ड आईएएस रनवीर सिंह, पूर्व एडीएम एल घनश्याम सिंह और अमीन ने किसानों को गुमराह

## खुलासा : होमगार्ड की हाजिरी लगाने में करोड़ों नहीं, अरबों रुपयों का खेल

नोएडा : होमगार्ड हाजिरी घोटाले में लखनऊ से गिरफ्तार ब्लॉक ऑर्गेनाइजर (बीओ) राजकुमार वर्मा ने कई राज उगले हैं। उसने खुलासा किया है कि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलीभगत कर प्रदेशभर में करोड़ों नहीं अरबों का घोटाला किया है। पुलिस ने राजकुमार के लिखित बयान पर जांच शुरू कर दी है। नोएडा में होमगार्ड हाजिरी घोटाले का खुलासा होने के बाद 19 नवंबर को सूरजपुर स्थित जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय में आगजनी हुई थी। आगजनी के दौरान वर्ष 2014 से अब तक का अधिकतर हाजिरी रिकॉर्ड जल गया था। इसके बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े में मंडलीय कमांडेंट अलीगढ़ राम नारायण

चौरसिया तत्कालीन जिला कमांडेंट गौतमबुद्धनगर, सहायक जिला कमांडेंट सतीश, प्लाटून कमांडर मोंटू, सतवीर यादव और शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था। फिर रिकॉर्ड में आग लगाने वाले अस्थायी प्लाटून कमांडेंट राजीव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हरकत में आई लखनऊ पुलिस ने चढ़े ब्लॉक ऑर्गेनाइजर (बीओ) राजकुमार वर्मा को गिरफ्तार किया था। राजकुमार ने पुलिस को जानकारी दी कि प्रदेशभर में हाजिरी में फर्जीवाड़ा करके अरबों रुपये का घोटाला किया गया है। हाजिरी घोटाले के इस खेल में लखनऊ स्थित मुख्यालय के कई अधिकारियों पर

भी गाज गिरना तय है। प्राथमिक जांच में पता चला कि फर्जी हाजिरी के बारे में विभाग के मुख्यालय में कार्यरत कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी थी। अधिकारियों और जिलास्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही अरबों रुपये का खेल किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया था कि ड्यूटी पर भेजे बिना ही मस्टर रोल में होमगार्ड की फर्जी हाजिरी लगा दी जाती थी मगर फर्जीवाड़े की एक और कड़ी सामने आई है। निलंबित बीओ राजकुमार ने पुलिस को बताया कि कई जिलों में एक ही होमगार्ड की दो जगहों पर ड्यूटी दिखाकर फर्जी तरीके से वेतन लिया गया जबकि वह सिर्फ एक ही जगह ड्यूटी करता था।

## बेसिक शिक्षा विभाग में होंगे अब ऑनलाइन ट्रांसफर

गाजियाबाद : बेसिक शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगे। शासन ने इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में पहल की है। जो शिक्षक अपना तबादला कराना चाहते हैं व विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उनका तबादला होगा। अब बिना ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया को विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी पवन भाटी ने बताया कि शासन ने शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसका सीधे तौर पर शिक्षकों को फायदा मिलेगा।



कर जमीन खरीदी थी। इसके बाद शासन से कई गुणा ज्यादा मुआवजा उठा लिया गया। यह घोटाला तत्कालीन मंडलायुक्त डॉ प्रभात कुमार की जांच में पकड़ा गया। उनकी जांच में दो पूर्व जिलाधिकारी भी शक के घेरे में हैं। एनएचआई को तभी से इन चार गांवों में 19 हेक्टेयर जमीन नहीं मिल रही थी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन के आदेश पर इस मामले की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कमेटी बनेगी।

## पीपीपी मॉडल पर सिद्धार्थ विहार गोल्फ कोर्स बनाने की तैयारी

वसुंधरा : आवास विकास परिषद सिद्धार्थ विहार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर गोल्फ कोर्स बनाएगा। 43 एकड़ के पार्क को अब गोल्फ कोर्स के रूप में विकसित करने का जिम्मा एक निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। परिषद के अधिकारियों के अनुसार नोएडा की तर्ज पर इसका निर्माण और

संचालन किया जाएगा। जल्द ही परिषद इसके लिए विभिन्न कंपनियों से निविदाएं मांग सकता है। आवास विकास परिषद की जमीन पर करीब 700 एकड़ की सिद्धार्थ विहार योजना में कई बहुमंजिला प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इनमें से परिषद के गंगा, यमुना और हिंडन एंक्लेव में लोग रह रहे हैं।

## जिले के अटॉर्नी धारकों को मालिकाना हक पाने के लिए करना होगा इंतजार

गाजियाबाद : पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारकों को मालिकाना हक पाने के लिए इंतजार करना होगा। शासन को अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री कराने के लिए अनुमति देने के मामले में निर्णय लेने में वक्त लगेगा। शहर की 19 कॉलोनियों में 10839 पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक हैं, जो अपने मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भू-राजस्व नियमावली और राजस्व नियमों के रजिस्ट्री धारक व्यक्ति ही संपत्ति का मालिक माना जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी से महज संपत्ति उपयोग का अधिकार मिलता है। राजस्व अभिलेखों में अटॉर्नी दर्ज नहीं होती। इस कारण इससे मालिकाना हक नहीं मिलता।

## आयुष्मान भारत योजना का ले सकेंगे लाभ

साहिबाबाद : ट्रांस हिंडन में बृहस्पतिवार को कई स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों के आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। इन कार्डों के माध्यम से लोगों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन दो वार्ड 73 में पार्षद सुनीता रावत रेड्डी के कार्यालय पर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान दो सौ से अधिक लोगों के कार्ड बनाए गए। भाजपा नेता पवन रेड्डी ने बताया कि गरीब तबके को इन कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिल पा रहा है। पार्षद सुनीता,

रजनीश, चंद्रभूषण, नरेश देवरानी, दरबान सिंह रावत, बलजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। उधर, पार्षद एवं नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य मनोज गोयल ने वैशाली सेक्टर 1 कामना मंदिर में प्राथमिक हेल्थ सेंटर द्वारा मेडिकल चेकअप तथा आयुष्मान योजना गोल्डन कार्ड के कैंप का आयोजन किया। हेल्थ सेंटर कि डॉक्टर रितु वर्मा तथा नरेंद्र वर्मा द्वारा पूरी टीम को लेकर लोगों का स्वास्थ्य चेकअप करा गया तथा दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। इस अवसर पर समाजसेवी सुभाष शर्मा, अवधेश कटियार, केएल शर्मा, भूपेंद्र, श्याम सुंदर, शुभम सिंह, दुष्यंत गौतम आदि लोग मौजूद रहे।

## अब आवेदन के आधार पर पीएम आवास का निर्माण

गाजियाबाद : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब मांग पर ही प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। इसके लिए जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लाएगा, वहां पहले आवेदन मांगेगा। ताकि यह पता चल सके कि यहां प्रधानमंत्री आवास लेने के कितने लोग इच्छुक हैं। फिर आवेदन की तुलना में आधे भवनों का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में शासन स्तर पर मंगलवार को समीक्षा बैठक हुई। इसमें जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा, मुख्य अभियंता विवेकानंद सिंह भी शामिल हुए। बैठक से लौटने के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन स्तर पर प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि भविष्य में जिस

क्षेत्र में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, वहां पहले आवेदन मांगे जाएं, ताकि यह पता चल सके कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए लोग इच्छुक भी हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि जीडीए के पास अब तक जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जमीन है। वहां प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के बाद ही तय किया जाएगा कि इस स्थान पर कितने प्रधानमंत्री आवास तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जितने भी आवेदन आएंगे, उनसे आधे ही भवन बनाए जाएंगे क्योंकि विभिन्न कारणों से करीब आधे आवेदन निरस्त हो जाते हैं। ऐसे में प्राधिकरण जरूरत से ज्यादा मकान नहीं बनाएगा।

साथ ही प्राधिकरण अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखेगा। ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जीडीए वीसी कंचन वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने से पहले इच्छुक आवेदकों के आवेदन मांगे जाएंगे। फिर आवेदन के आधार पर आधे आवास बनाए जाएंगे। निर्माणार्थीन प्रोजेक्ट को छोड़कर अन्य प्रोजेक्ट पर यहीं नियम लागू होगा। जीडीए मधुबन—बापूधाम योजना में 856 और डासना में 432 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मधुबन—बापूधाम योजना के लिए साढ़े चार हजार आवेदन आए थे।

**BUREAU OFFICE**  
**PRATEEK BHARGAVA**  
Bureau Chief  
5, Ashok Vihar, 3rd Floor,  
GMS Road, Nr. Ballupur  
Chowk, Dehradun.  
Mobile: +91 8130640011  
Email: prateekb@tbcbgzb.com  
[www.tbcbgzb.com](http://www.tbcbgzb.com)  
Contact for Press Release  
and Advertisements

**BUREAU OFFICE**  
**VIKRAM KUMAR**  
Bureau Chief  
12/516, Friends Co-operative  
Society Vasundhara,  
Ghaziabad (UP)  
Mobile: +91 8130640077  
Email: vikram@tbcbgzb.com  
[www.tbcbgzb.com](http://www.tbcbgzb.com)  
Contact for Press Release  
and Advertisements